समाज परिवर्तन समुदाय और अन्य

बनाम

कर्नाटक राज्य और अन्य

(आई.ए. संख्या 247, आई.ए. संख्या 247 में आई.ए. संख्या 250 और आई.ए. संख्या 247 में आई.ए. संख्या 252)

में

(रिट याचिका (सी) संख्या 562/2009)

21 मार्च, 2017

[रंजन गोगोई, प्रफुल्ल सी. पंत और ए. एम. खानविलकर, जे. जे.]

पर्यावरणः

प्रदूषण-अवैध खनन- अवैध खनन-अभूतपूर्व अवैध खनन के कारण पर्यावरण का बड़े पैमाने पर क्षरण-उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए सुधारात्मक और शमनकारी सामाजिक-आर्थिक उपाय-आदेश के माध्यम से। 18.4.2013 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित, प्रत्यर्थी-राज्य के तीन जिलों में पट्टेदारों को खनन की बिक्री आय का 10 प्रतिशत एक विशेष प्रयोजन वाहन (एस. पी. वी.) को अंत में हस्तांतरण के लिए निगरानी समिति को योगदान करने का निर्देश दिया गया, जो इस तरह के सुधारात्मक और शमनकारी उपायों के निष्पादन के लिए गठित किया गया था-प्रत्यर्थी-राज्य ने 2015 के अधिनियम की धारा 9 (बी) के तहत खनन से प्रभावित प्रत्येक जिले में एक जिला खनिज फाउंडेशन (डी. एम. एफ.) की स्थापना की, पट्टेदारों को डी. एम. एफ. को भी भुगतान करने का निर्देश दिया-पट्टेदारों की याचिका कि डी. एम. एफ. के अतिव्यापी उद्देश्यों को देखते हुए और जिस उद्देश्य के लिए न्यायालय ने एस. पी. वी.

के निर्माण के लिए आदेश पारित किए थे, पट्टेदारों को अब बिक्री आय का 10 प्रतिशत निगरानी समिति/एस. पी. वी. को योगदान करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

समर्थनीय नहीं-प्रत्यर्थी-राज्य के तीन जिलों में प्राकृतिक संपत्ति और पर्यावरण की व्यवस्थित, असाधारण और अभूतपूर्व लूट हुई है-ऐसी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए एस. पी. वी. की आवश्यकता पर विचार किया गया था कि निगरानी समिति के पास जमा किए गए विशेष धन में अवैध खनन की आय को इस तरह की अवैध गतिविधियों के कारण जो नुकसान हुआ है, उसके मनोरंजन के लिए तैनात किया जाना था-भारी अनुपात में धन आवश्यक होगा-ऐसी स्थिति में पट्टेदार जो प्रकृति के क्षरण और विनाश से भी दूर से जुड़े हो सकते हैं, उन्हें अपनी वर्तमान बिक्री आय से निगरानी समिति को योगदान देकर क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया में अपने हिस्से का भुगतान करना जारी रखना चाहिए। यहां तक कि नए पट्टेदार जो इस तरह के क्षरण में शामिल नहीं हैं, वे भी सुधार और बहाली की प्रक्रिया में योगदान दे रहे हैं-खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015-धारा 9 बी-जिला खनिज फाउंडेशन 2016-नियम.3।

प्रदूषण-अवैध लौह अयस्क खनन-सुधारात्मक और शमनकारी सामाजिक-आर्थिक उपाय-उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के अनुसार केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सी. ई. सी.) के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा तैयार खनन प्रभाव क्षेत्र (सी. ई. पी. एम. आई. जेड.) के लिए व्यापक पर्यावरण योजना (सी. ई. पी. एम. आई. जेड.) का कार्यान्वयन-आयोजितः पूरी सी. ई. पी. एम. आई. जेड. योजना को एक बार में मंजूरी देने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह की मंजूरी चरणों में दी जा सकती है-प्रारंभिक गतिविधियों की पहचान की गई है, अर्थात्, (i) कन्वेयर बेल्ट प्रणाली का निर्माण; (ii) रेलवे साइडिंग और iii) रेलवे सब-लाइनों को प्राथमिकता देने की

आवश्यकता है क्योंकि सड़क द्वारा लौह अयस्क की खुली आवाजाही के कारण पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में यही सबसे महत्वपूर्ण कदम है।

आई .ए. को खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

1.1 पहली बार में, यह प्रतीत हो सकता है कि जिला खनिज फाउंडेशन के उद्देश्यों और विशेष प्रयोजन वाहन (एस. पी. वी.) की स्थापना में न्यायालय के आदेश द्वारा विचार किए गए उद्देश्य के बीच कुछ मात्रा में अतिव्यापी है। हालाँकि, न्यायालय के आदेशों के बाद किए गए वैधानिक अधिनियमों और अभ्यासों को किसी भी खनन संचालन के लिए आकस्मिक खनिज शोषण की चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता के बारे में विधायी राय की अभिव्यक्ति के रूप में समझना होगा। प्रत्येक खनन गतिविधि के परिणामस्वरूप हानिकारक प्रभाव होते हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता होती है और इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से होने वाले पर्यावरण के विनाश को कम करने की आवश्यकता होती है। यह वह विशिष्ट दोहराव है जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 9 बी को शामिल करके प्रावधानों में संशोधन करके किया गया है। और इसके तहत बनाए गए जिला खनिज नियम, 2016। बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर में जो हुआ था, उस पर इस न्यायालय ने दिनांकित 18.04.2013 के फैसले के पैराग्राफ 37 में ध्यान दिया है, अर्थात व्यवस्थित रूप से, प्राकृतिक संपदा और पर्यावरण की असाधारण और अभूतपूर्व लूट। इस न्यायालय ने विशेष रूप से पैराग्राफ 37 में कहा है कि "स्थिति असाधारण होने के कारण उपचार भी असाधारण होना चाहिए।" ऐसी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए खनन प्रभाव क्षेत्र ("सी. ई. पी. एम. आई. जेड".) के लिए व्यापक पर्यावरण योजना की आवश्यकता और निगरानी समिति के साथ ऋण में धन से एक एस. पी. वी. द्वारा इसके कार्यान्वयन पर विचार किया गया। निगरानी समिति के पास जमा की गई विशेष धनराशि अवैध खनन की आय है, जिसे इस तरह की अवैध गतिविधियों के कारण जो नुकसान हुआ है, उसके

मनोरंजन के लिए तैनात किया जाना था। उपरोक्त उद्देश्य के लिए सी. ई. पी. एम. आई. जेड. तैयार करने और उसके बाद इसे लागू करने की आवश्यकता थी। योजना के कार्यान्वयन की स्थिति अभी शुरू नहीं हुई है। भारी अनुपात में धन की आवश्यकता होगी। एक पूर्ण और स्पष्ट तस्वीर अभी सामने आनी बाकी है। ऐसी स्थिति में पट्टेदार जो प्रकृति के क्षरण और विनाश से दूर से भी जुड़े हो सकते हैं, उन्हें अपनी वर्तमान बिक्री आय से प्रबंधन समिति को योगदान देकर पुनर्भुगतान की प्रक्रिया में अपने हिस्से का भुगतान करना जारी रखना चाहिए। यहां तक कि नए पट्टेदार जो इस तरह के क्षरण में शामिल नहीं हैं, वे भी सुधार और बहाली की प्रक्रिया में योगदान दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में, यह नहीं देखा जा सकता है कि सभी मौजूदा पट्टेदारों को निगरानी समिति/एस. पी. वाई. को बिक्री आय का 10 प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता वाले पहले के आदेशों को कैसे बदला जा सकता है/संशोधित किया जा सकता है या उनसे अलग किया जा सकता है। [पैरा 12) [586-ए-एच)

2.1 दूसरा मुद्दा इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों के संदर्भ में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सी. ई. सी.) के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए सी. ई. पी. एम. आई. जेड. को मंजूरी देने से संबंधित है। यदि उपरोक्त योजना को मंजूरी दी जाती है, तो इसे एस. पी. वी. यानी कर्नाटक खनन पर्यावरण बहाली निगम ("के. एम. ई. आर. सी".) के माध्यम से लागू किया जाना है, जिसका गठन तब से किया गया है। [पैरा 14) (589-बी)

2.2 इस योजना के तहत प्रस्तावित कार्यों को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित और दूसरा एकीकृत खनन और रेलवे अवसंरचना, औद्योगिक अवसंरचना और चिकित्सा अवसंरचना के लिए। [पैरा 15) [587-सी]

2.3 सी. ई. पी. एम. आई. जेड, इस स्तर पर, वास्तव में एक दृष्टि दस्तावेज की प्रकृति में है, जिसमें सभी ठोस उपायों, कदमों और प्रस्तावों पर बाद के चरण में काम किया जाना बाकी है, यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का चरण, और योजना के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है, सिवाय इसके कि यह कहने के कि जहां तक सामाजिक-आर्थिक उपायों का संबंध है, बहुत व्यापक और मोटे तौर पर, विभिन्न शीर्ष जिनके तहत बहाली और सुधार कार्य करने का प्रस्ताव है, जो बाद में अंतिम विवरण पर काम करने के अधीन है, पर्याप्त रूप से व्यापक प्रतीत होता है। [पैरा-22) [595-डी-ई]

2.4 इस स्तर पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर समग्र रूप से सी. ई. पी. एम. आई. जेड. को मंजूरी देने के बजाय, इस मामले में विचारों को तब तक रोका जा रहा है जब तक कि प्रत्येक व्यापक शीर्ष के संबंध में अधिक व्यापक विवरण उपलब्ध नहीं हो जाते, जिसके तहत सुधारात्मक और शमनकारी उपाय करने का प्रस्ताव है। हालांकि, एक ही समय में, एकीकृत खनन और प्रस्तावित रेलवे बुनियादी ढांचे के हिस्से को मंजूरी दी जाती है, अर्थात्, कन्वेयर बेल्ट प्रणाली का निर्माण; रेलवे साइडिंग और रेलवे उप-लाइन। यह केवल एक बार है जब उपरोक्त बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर निर्णय लिया जाता है और इसके निष्पादन के मामले में ध्यान देने योग्य प्रगति होती है, तो अन्य सुधारात्मक और शमनकारी सामाजिक-आर्थिक उपायों की कोई प्रासंगिकता हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कन्वेयर बेल्ट, रेलवे साइडिंग और रेलवे सब-लाइन पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम होंगे जो सड़क मार्ग से लौह अयस्क की खुली आवाजाही के कारण बना रहता है। लौह अयस्क की नियंत्रित और विनियमित आवाजाही के बाद ही अन्य सामाजिक-आर्थिक उपाय किए जाने चाहिए ताकि सार्थक परिणाम मिल सकें। [पैरा 22) [595-जी-एच; 596-ए-बी]

2.5 दूसरे शब्दों में, पूरी सी. ई. पी. एम. आई. जेड. योजना को एक बार में अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह की मंजूरी पर विचार किया जा सकता है और चरणों में दी जा सकती है। प्रारंभिक गतिविधि की पहचान की गई है, अर्थात् कन्वेयर बेल्ट प्रणाली का निर्माण; रेलवे साइडिंग और रेलवे उप-लाइनों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। [पैरा 22) [596-डी) सम} परिवर्तन समुद्र और अन्य। v. कर्नाटक राज्य और अन्य। (2013) 8 एस. सी. सी. 154: [2013] 6 एस. सी. आर. 810-पर निर्भर था। [2013] 6 एस. सी. आर. 810 मामला कानून संदर्भ पैरा 3 पर निर्भर था

आई. ए. सं. 247 में आई. ए. सं. 247, आई. ए. सं. 250 और आई. ए. सं.: भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत 2009 की रिट याचिका (सी) संख्या 562 में आई. ए. संख्या 247 में 252।

एन. के. कौल, मनिंदर सिंह, ए. एस. जी., श्याम दीवान (ए. सी.), राजू रामचंद्रन, सी. ए. सुंदरम, चंदर उदय सिंह, गोपाल जैन, हुज़ेफा अहमदी, कृष्णन वेणुगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। ए. डी. एन. राव, सिद्धार्थ चौधरी, ए. सी. एस., भुवन मिश्रा, सुश्री आशा जी. नायर, कबीर हाथी, समर कछवाहा, जी. एस. मक्कर, सुश्री विमला सिन्हा, एस. ए. हसीब, सुश्री अनिल कटियार, पी. के. डे, अजय शर्मा, आर. बालासुब्रमण्यम, आर. आर. राजेश, राज बहादुर, एम. के. मारोरिया, गोविंद जी, प्रशांत भूषण, सुश्री अनीता शिनॉय, सुश्री धारिणी एस., के. राघवचार्युलु; कैलाश पांडे, रंजीत सिंह, सुश्री जूली, के. वी. श्रीकुमार, आकाश बजाज, संजीव के. कपूर, (मिस के लिए। खैतईः टी एंड कंपनी), रोहित शर्मा, आदित्य नारायण, रौणक नायक, उपस्थित दलों के लिए पी. भदानी, विजेंद्र कसाना, चांद क्लिरेशी, एम. पी. सिद्दीकी, के. एन. फणींद्र, निनाद लॉड, करण माथुर, अंजुमन त्रिपाठी, जयंत मोहन, अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय रंजन गोगोई, जे. द्वारा दिया गया था।

1. वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदनों में निर्धारण के लिए दो संबंधित और संबंधित मुद्दे उत्पन्न हुए हैं।

2. पहला, कर्नाटक राज्य के बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों में खनन प्रभाव क्षेत्र (संक्षेप में "सीईपीएमआईजेड" और इसके बाद "योजना" के रूप में संदर्भित) के लिए व्यापक पर्यावरण योजना को लागू करने के लिए गठित किए गए विशेष प्रयोजन वाहन ("एस. पी. वी".) को अंतिम हस्तांतरण के लिए निगरानी समिति को खनन की बिक्री आय का 10 प्रतिशत भुगतान जारी रखने पर खनन पट्टेदारों की आपत्ति के संबंध में है। वर्तमान में, यह ध्यान देने के लिए पर्याप्त होगा कि इस न्यायालय ने समय-समय पर पारित अपने आदेशों द्वारा पर्यावरण के बड़े पैमाने पर क्षरण से निपटने के लिए सुधारात्मक और शमनकारी कार्यों/उपायों के निष्पादन के उद्देश्य से एक विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना का निर्देश दिया था, जो उपरोक्त तीन जिलों में संचालित खनन पट्टों में प्रासंगिक समय पर हुए अभूतपूर्व अवैध खनन के कारण हुआ था। इस निगम ने समय-समय पर आवश्यक कार्यों के सभी विवरणों को रेखांकित करते हुए एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। शुरू की जाने वाली; कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा इसे लागू करने की प्रक्रिया; लेखा प्रक्रियाएँ आदि। और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (संक्षेप में "सी. ई. सी".) के परामर्श से इसे इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए। इस न्यायालय का यह भी विचार था कि एस. पी. वी. के लिए तैयार किए जाने वाले सी. ई. पी. एम. आई. जेड. के अनुसार सुधारात्मक और शमनकारी उपायों को सक्षम करने के लिए धन मुख्य रूप से (ए) खनिजों की बिक्री आय का 10 प्रतिशत; (बी) अवैध खनन आदि के लिए मुआवजे से आएगा। और (ग) निगरानी समिति द्वारा प्राप्त अन्य प्राप्तियों को समय-समय पर एस. पी. वी. को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया जाना।

3. इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित किए गए विभिन्न आदेशों को दिनांक 1 के निर्णय और आदेश में इस न्यायालय की अंतिम मंजूरी मिली थी, जिसने अंततः 2009 की रिट याचिका (सी) संख्या 562 को समाप्त कर दिया, जिसका शीर्षक था "समाज परिवर्तन समुद्र और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य"।

4. उपरोक्त आदेशों के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने एक विशेष प्रयोजन वाहन का गठन किया है जिसे कर्नाटक खनन पर्यावरण बहाली निगम (संक्षेप में "के. एम. ई. आर. सी".) के रूप में जाना जाता है, जिसके अध्यक्ष कर्नाटक सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। सी. ई. पी. एम. आई. जेड. अर्थात योजना तब से तैयार की गई है और वर्तमान में न्यायालय की मंजूरी की प्रतीक्षा कर रही है जो वर्तमान में मामले का अगला/जुड़ा हुआ पहलू है।

5. जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, आवेदक, फेडरेशन ऑफ इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री, सदर्न रीजन ("एफ. आई. एम. आई.-सदर्न रीजन") द्वारा की गई प्रार्थना और एक अन्य पट्टेदार द्वारा विधिवत समर्थित। वेदांता, संक्षेप में, यह है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2015 के बाद अधिनियम में धारा 9 बी लाई गई थी, जो खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित प्रत्येक जिले में एक जिला खनिज फाउंडेशन स्थापित करने की आवश्यकता है। धारा 9 बी (5) और (6) के तहत पट्टेदारों को जिला खनिज फाउंडेशन (संक्षेप में "डीएमएफ") को रॉयल्टी के ऐसे प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करना आवश्यक है जो ऐसी रॉयल्टी के एक तिहाई से अधिक न हो, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए।

6. खान मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक आई. डी. 3 की एक अधिसूचना द्वारा निर्धारित किया है कि आई. डी. 1 से पहले दिए गए पट्टों के संबंध में डी. एम. एफ. को देय राशि रॉयल्टी का 30 प्रतिशत यानी बिक्री मूल्य का 5.5 प्रतिशत (लगभग)

होगी और आई. डी. 2 के बाद दिए गए पट्टों के संबंध में डी. एम. एफ. में योगदान रॉयल्टी का 10 प्रतिशत यानी बिक्री मूल्य का 1.5 प्रतिशत होगा। नतीजतन, वर्तमान में श्रेणी ए और श्रेणी बी की खदानों के पट्टों को निगरानी समिति/एस. पी. वाई. को देय बिक्री मूल्य के 10 प्रतिशत के अलावा ऐसे मूल्य का लगभग 4.5 प्रतिशत जिला खनिज फाउंडेशन को देना पड़ता है। एफ. आई. एम. आई.-(दक्षिणी क्षेत्र) द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अधिसूचना दिनांक 11.01.2016 द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन नियम, 2016 को कर्नाटक सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। नियम 3 में निर्धारित जिला खनिज फाउंडेशन के उद्देश्य इस प्रकार हैंः

> "3. फाउंडेशन के उद्देश्य-जिला खनिज फाउंडेशन का उद्देश्य जिलों में खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्रों के हित और लाभ के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से काम करना होगाः-(1) खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी परियोजनाओं या कार्यक्रमों को लागू करना।
>
> (2) खनन के दौरान और बाद में, खनन जिलों में लोगों के पर्यावरण, स्वास्थ्य और सामाजिक-अर्थशास्त्र पर प्रतिकूल प्रभावों को कम करना या कम करना; और
>
> (3) खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना।"

डी. एम. एफ., 2016 के नियम 18 में उस उद्देश्य को निर्धारित किया गया है जिसके लिए धन का उपयोग किया जाएगा और जिसमें पेयजल आपूर्ति, शिक्षा, महिलाओं और बच्चों का कल्याण, वृद्ध और विकलांग व्यक्ति, कौशल विकास, स्वच्छता, भौतिक अवसंरचना, सिंचाई और ऊर्जा और जलग्रहण विकास शामिल हैं।

7. उपरोक्त घटनाक्रमों के आलोक में आवेदक द्वारा आई. ए. सं. 247 में यह तर्क दिया गया है कि समय-समय पर जारी किए गए न्यायालय के आदेशों के तहत तैयार किए गए सी. ई. पी. एम. आई. जेड. के संदर्भ में सुधारात्मक और शमनकारी उपायों के पीछे का उद्देश्य जिला खनिज फाउंडेशन के निर्माण के पीछे के उद्देश्य के समान है। तदनुसार, आवेदक एफ. आई. एम. आई. (दक्षिणी क्षेत्र) ने इस न्यायालय के पहले के आदेशों के स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध किया है कि कर्नाटक राज्य में लौह अयस्क पट्टेदारों को अब निगरानी समिति या एस. पी. वाई. को बिक्री आय का 10 प्रतिशत योगदान करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिसकी तारीख से कहा गया है कि पट्टेदार खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 2015 की धारा 9 बी के तहत जिला खनिज फाउंडेशन को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो गए हैं, जैसा कि संशोधित किया गया है।

8. जवाब में, भारत संघ और कर्नाटक राज्य ने किसी भी राहत/स्पष्टीकरण के अनुदान का विरोध किया है, जैसा कि एफ. आई. एम. आई.-दक्षिणी क्षेत्र द्वारा अनुरोध किया गया है। भारत संघ के अनुसार, न्यायालय के आदेशों के तहत विचार किया गया एस. पी. वाई., तीन जिलों में विभिन्न सुधारात्मक और शमनकारी उपाय करने के उद्देश्य से, जो तब से स्थापित किया गया है, पर्यावरण की बड़े पैमाने पर लूट और अभूतपूर्व पैमाने पर हुए अवैध खनन से इस क्षेत्र को हुए परिणामी सामाजिक-आर्थिक नुकसान की अगली कड़ी है। भारत संघ ने कहा है कि कर्नाटक के तीन खनन जिलों में प्रकृति और पर्यावरण के असाधारण क्षरण को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय द्वारा प्रकृति और पर्यावरण को उसके मूल रूप में मरम्मत, पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापित करने के लिए एस. पी. वाई. का गठन किया गया है। एस. पी. वाई. का गठन एक ऐसी स्थिति का जवाब देने के लिए किया गया है जो असाधारण थी और विशेष रूप से

बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर जिलों के खनन क्षेत्रों तक ही सीमित थी। भारत संघ द्वारा 5.9.2016 पर दायर हलफनामे के पैराग्राफ 10 में, यह निम्नानुसार कहा गया हैः

> "यह प्रस्तुत किया जाता है कि एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9 बी द्वारा परिकल्पित जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) एक ऐसा निकाय है जिसकी परिकल्पना खनन प्रभावित क्षेत्रों और आबादी के लाभ के लिए की गई है, जहां खनन जिम्मेदार तरीके से, सीमाओं के भीतर और विभिन्न अनुमोदनों और मंजूरी जैसे वन मंजूरी और पर्यावरण मंजूरी द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन किया जाता है। डी. एम. एफ. तंत्र पूरे देश में एक समान आधार पर लागू होता है। यह पर्यावरण पर पड़ने वाले परिणामों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए किए गए बड़े पैमाने पर, गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाह खनन से उत्पन्न किसी भी क्षेत्र विशिष्ट असाधारण स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया तंत्र नहीं है जैसा कि कर्नाटक में हुआ था।

9. विशेष रूप से, हलफनामे के पैराग्राफ 15 में, भारत संघ ने कहा हैः "उपरोक्त सभी को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि डी. एम. एफ. का कभी भी सी. ई. पी. एम. आई. जेड. के विकल्प के रूप में काम करने का इरादा नहीं था, और वास्तव में कभी भी काम नहीं कर सकता है।"

10. कर्नाटक राज्य ने भी एफ. आई. एम. एल.-दक्षिणी क्षेत्र द्वारा मांगी गई किसी भी राहत के अनुदान पर अपनी विस्तृत आपत्तियां दर्ज की हैं। भारत संघ द्वारा अपने हलफनामे में लिए गए रुख के अलावा, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, कर्नाटक राज्य ने बताया है कि सी. ई. पी. एम. आई. जेड. ने सी. ई. सी. की सिफारिशों पर सी. ई. सी. के परामर्श से तैयार किया और अदालत को प्रस्तुत किया

कि अब से पट्टेदार को निगरानी समिति/एस. पी. वाई. को बिक्री आय का 5.5 प्रतिशत भुगतान करने का निर्देश दिया जाना चाहिए (इस संबंध में विवरण बाद में देखा जाएगा)। पूरी सी. ई. पी. एम. आई. जेड. योजना, विशेष रूप से, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए वित्तीय अनुमान उसी आधार पर तैयार किए गए हैं। एफ. आई. एम. आई.-साउथेम क्षेत्र द्वारा की गई प्रार्थना के परिणामस्वरूप पूरी योजना बाधित होगी और इसके विचार/नियोजित कार्यान्वयन को खतरे में डाल देगा। इसके अलावा, कर्नाटक राज्य के अनुसार, ए और बी श्रेणियों के पट्टेदारों द्वारा निगरानी समिति/एस. पी. वाई. में योगदान को बंद करने का कोई भी आदेश उन अन्य पट्टेदारों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा जिन्होंने हाल ही में पट्टे प्राप्त किए हैं और जो भविष्य में ऐसे पट्टे प्राप्त करेंगे, क्योंकि ऐसे पट्टों के लिए बिक्री आय का एक प्रतिशत कर्नाटक राज्य द्वारा योगदान किया जाना है और एस. पी. वाई. को उपलब्ध कराया जाना है। राज्य का तर्क है कि इस तरह की स्थिति के परिणामस्वरूप अत्यधिक असमान स्थिति पैदा होगी क्योंकि पर्यावरण क्षरण के लिए जिम्मेदार मौजूदा पट्टेदार, पर्यावरण को बहाल करने के लिए सुधारात्मक और शमनकारी कदम उठाने में एस. पी. वाई. को आगे कुछ भी योगदान नहीं देंगे, जबकि नए पट्टेदार जैसे श्रेणी पट्टेदार, जो इतने जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं, उनका योगदान होगा।

11. सी. ई. सी. ने अपने दिनांकित 27.04.2016 के जवाब में, हालांकि, इस मामले पर थोड़ा अलग दृष्टिकोण अपनाया है। सी. ई. सी. की समझ में जिला खनिज फाउंडेशन के उद्देश्यों और जिस उद्देश्य के लिए न्यायालय ने उल्लिखित कार्य के साथ एस. पी. वाई. के निर्माण के लिए आदेश पारित किए थे, जैसा कि ऊपर देखा गया है, के बीच एक उचित मात्रा में अतिव्यापी है। सी. ई. सी. के अनुसार, मौजूदा पट्टों के लिए, वर्तमान में भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी का 30 प्रतिशत बिक्री आय का लगभग 4.5 प्रतिशत है। तदनुसार, सी. ई. सी. ने सुझाव दिया है कि मौजूदा पट्टेदार

बिक्री आय का 5.5 प्रतिशत (10 प्रतिशत के बजाय) निगरानी समिति/एस. पी. वाई. को दे सकते हैं और साथ ही साथ जिला खनिज फाउंडेशन को रॉयल्टी के 30 प्रतिशत की सीमा तक भुगतान के वैधानिक दायित्व का निर्वहन करना जारी रख सकते हैं, जो बिक्री आय के लगभग 4.5 प्रतिशत के बराबर है।

12. हमने इस मामले पर विचार किया है। हमने इस न्यायालय के पिछले आदेशों पर भी ध्यान दिया है, विशेष रूप से अंतिम आदेश दिनांक 18.04.2013 (पैराग्राफ 37); धारा 9 बी के प्रावधानों को शामिल करके खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में संशोधन के पीछे के उद्देश्य; और कर्नाटक सरकार द्वारा 11.01.2016 पर अधिसूचित जिला खनिज नियम, 2016 के नियम 3 द्वारा प्रदान किए गए जिला खनिज फाउंडेशन के उद्देश्यों सहित समय-समय पर जारी की गई अधिसूचनाएं। हालांकि, पहली बार में, यह प्रतीत हो सकता है कि जिला खनिज फाउंडेशन के उद्देश्यों और एस. पी. वी. की स्थापना में न्यायालय के आदेश द्वारा विचार किए गए उद्देश्य के बीच कुछ मात्रा में अतिव्यापी है, इस न्यायालय की टिप्पणियों से दिनांकित 18.04.2013 (ऊपर) के फैसले के पैराग्राफ 37 में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। न्यायालय के आदेशों के बाद किए गए वैधानिक अधिनियमों और अभ्यासों को किसी भी खनन संचालन के लिए आकस्मिक खनिज शोषण की चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता के बारे में विधायी राय की अभिव्यक्ति के रूप में समझना होगा। प्रत्येक खनन गतिविधि के परिणामस्वरूप हानिकारक प्रभाव होते हैं जिन्हें ठीक करने की आवश्यकता होती है और इस प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से होने वाले पर्यावरण के विनाश को कम करने की आवश्यकता होती है। यह विशिष्ट पुनरावृत्ति है जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों में संशोधन द्वारा की गई है। बेल्लारी, चित्रदुर्ग और तुमकुर में जो हुआ था, उस पर इस न्यायालय ने पहले ही दिनांक 1 के फैसले के पैराग्राफ 37 में ध्यान दिया है, अर्थात प्राकृतिक संपदा और

पर्यावरण की व्यवस्थित, असाधारण और अभूतपूर्व लूट। इस न्यायालय ने पैराग्राफ 37 में विशेष रूप से कहा है कि "स्थिति असाधारण होने के कारण उपचार भी असाधारण होना चाहिए।" ऐसी असाधारण स्थिति से निपटने के लिए सी. ई. पी. एम. आई. जेड. की आवश्यकता और निगरानी समिति के साथ ऋण में धन से एक विशेष प्रयोजन वाहन द्वारा इसके कार्यान्वयन पर विचार किया गया था। निगरानी समिति के पास जमा की गई विशेष धनराशि अवैध खनन की आय है, जिसे इस तरह की अवैध गतिविधियों के कारण जो नुकसान हुआ है, उसके मनोरंजन के लिए लगाया जाना था। उपरोक्त उद्देश्य के लिए सी. ई. पी. एम. आई. जेड. तैयार करने और उसके बाद इसे लागू करने की आवश्यकता थी। योजना के कार्यान्वयन की स्थिति अभी शुरू नहीं हुई है। भारी अनुपात में धन की आवश्यकता होगी। एक पूर्ण और स्पष्ट तस्वीर अभी सामने आनी बाकी है। ऐसी स्थिति में पट्टेदार जो प्रकृति के क्षरण और विनाश से दूर से भी जुड़े हो सकते हैं, उन्हें अपनी वर्तमान बिक्री आय से प्रबंधन समिति को योगदान देकर पुनर्भुगतान की प्रक्रिया में अपने हिस्से का भुगतान करना जारी रखना चाहिए। यहां तक कि नए पट्टेदार जो इस तरह के क्षरण में शामिल नहीं हैं, वे भी सुधार और बहाली की प्रक्रिया में योगदान दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में, हम यह नहीं देखते हैं कि हम अपने पहले के आदेशों को कैसे बदल सकते हैं या संशोधित कर सकते हैं, जिसमें सभी मौजूदा पट्टेदारों को बिक्री आय का 10 प्रतिशत भुगतान करने की आवश्यकता होती है और/या जो पहले से ही आदेश दिया गया है, उसके भुगतान की आवश्यकता से हटना पड़ता है, अर्थात् बिक्री आय का 10 प्रतिशत निगरानी समिति/एस. पी. वाई. को।

13. पूर्वगामी को ध्यान में रखते हुए, अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 247 और संबंधित अंतर्वर्ती आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं।

14. दूसरा मुद्दा जिससे निपटा जाना है, वह सी. ई. पी. एम. आई. जेड. को मंजूरी देने के संबंध में है जिसे राज्य सरकार द्वारा सी. ई. सी. के परामर्श से इस

न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित विभिन्न आदेशों के संदर्भ में तैयार किया गया है। यदि उपरोक्त योजना को मंजूरी दी जाती है, तो इसे विशेष प्रयोजन वाहन यानी कर्नाटक खनन पर्यावरण बहाली निगम (संक्षेप में "के. एम. ई. आर. सी".) के माध्यम से लागू किया जाना है, जिसका गठन तब से किया गया है।

15. हमने सी. ई. पी. एम. आई. जेड. का अध्ययन किया है जिसे सी. ई. सी. द्वारा 29.04.2016 की रिपोर्ट द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। बहुत व्यापक रूप से, इस योजना के तहत प्रस्तावित कार्यों को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित और दूसरा एकीकृत खनन और रेलवे अवसंरचना, औद्योगिक अवसंरचना और चिकित्सा अवसंरचना के लिए। नीचे निकाला गया चार्ट इंगित करेगा कि योजना में क्या समझा गया है, कुल अनुमानित लागत और धन का स्रोत। सी. ई. पी. एम. आई. जेड. योजना (दस साल के दौरान) के प्रभाव के संदर्भ में खर्चा

16. इनमें से रु. सी. ई. पी. एम. आई. जेड. के 10 वर्षों की अवधि में कार्यान्वयन की कुल लागत के रूप में परिकल्पित 15 करोड़ रुपये, वर्तमान में उपलब्ध धनराशि और जहां तक एस. पी. वी. का संबंध है, भविष्य में आने वाली राशि, जैसा कि सी. ई. सी. की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है, इस प्रकार हैः

17. उपरोक्त इंगित करेगा कि जबकि कुल रु। एस. पी. वी. द्वारा खर्च की जाने वाली प्रस्तावित लागत 11,842 करोड़ रुपये है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उपलब्ध राशि को ध्यान में रखते हुए, यानी 0,336 करोड़ रुपये की कमी है। 1, 560 करोड़। लागत बचत और परियोजना लागत में कमी से इसकी भरपाई करने पर विचार किया गया है। समय-समय पर विभिन्न राशियों पर उपार्जित ब्याज और विभिन्न शीर्षों के तहत गणना की गई लागतों के अधिक अनुमान की संभावित अपेक्षा पर.

18. सी. ई. सी. ने अपनी रिपोर्ट में और विद्वान न्यायमित्र ने सी. ई. सी. के साथ संयुक्त रूप से प्रस्तुत अपने लिखित नोट में सुझाव दिया है कि योजना को निम्नलिखित शर्तों में अनुमोदित किया जा सकता हैः

"(i) कर्नाटक राज्य द्वारा तैयार किए गए सीईपीएमआईजेड को के. एम. ई. आर. सी. के माध्यम से कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया जा सकता है। के. एम. ई. आर. सी. को सी. ई. पी. एम. आई. जेड. में परिकल्पित किसी भी योजना/परियोजना को जोड़ने/संशोधित करने के लिए इस माननीय न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है;

(ii) निगरानी समिति को 500 करोड़ रुपये हस्तांतरित करने की अनुमति दी जा सकती है। इसके पास पड़ी निधियों में से 7,000 करोड़ रुपये से लेकर इसके द्वारा प्राप्त ब्याज सहित

(iii) "सीईपीएमआईजेड के लिए कार्यान्वयन और निगरानी और पर्यवेक्षण ढांचा" (सीईसी रिपोर्ट दिनांक 29.04.2016 के पृष्ठ 1ओ1 पर अनुलग्नक ए-3) को के. एम. ई. आर. सी. और राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी बनाया जा सकता है;

(iv) के. एम. ई. आर. सी. के खातों का वार्षिक लेखा-परीक्षण कैग द्वारा किया जाएगा;

(v) के. एम. ई. आर. सी. के प्रशासनिक खर्चों पर कार्यों पर वार्षिक व्यय की 5 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की जा सकती है;

(vi) राज्य सरकार द्वारा की गई प्रतिबद्धता कि सभी नीलाम पट्टों (नए पट्टे/डालमिया पट्टे/श्रेणी ए/श्रेणी बी पट्टे) से प्राप्त वार्षिक प्रीमियम राशि का 25 प्रतिशत आदेश में दर्ज किया जा सकता है;

(vii) यह स्पष्ट किया जा सकता है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा अनुमोदित 'आर एंड आर योजनाओं की तैयारी के लिए दिशानिर्देश' नीलामी के माध्यम से दिए गए सभी नए पट्टों पर समान रूप से लागू होते हैं/एम. एम. डी. आर. आर. अधिनियम की धारा 10ए (2) और 10ए (2) (सी) के तहत। ;

(viii) माननीय न्यायालय यह स्पष्ट करने पर विचार कर सकता है कि चित्रदुर्ग जिलों में रेलवे साइडिंग और/या वैकल्पिक सड़क के निर्माण के लिए आवश्यक कोई भी राशि के. एम. ई. आर. सी. द्वारा केवल पूंजीगत लागत वसूली के आधार पर खर्च की जाएगी। ;

(ix) सी. ई. पी. एम. आई. जेड. के कार्यान्वयन के संबंध में नियमित तिमाही प्रगति रिपोर्ट के. एम. ई. आर. सी. के अध्यक्ष द्वारा इस माननीय न्यायालय के समक्ष दायर की जाएगी। ;

(x) बंद पाइप डाउनहिल कन्वेयर सिस्टम को उनकी लागत पर स्थापित किया जाएगाः

(a) 1 एम. एम. टी. और उससे अधिक के एम. पी. ए. पी. के साथ श्रेणी-ए/श्रेणी-बी पट्टों में से प्रत्येक और 8 वर्ष और उससे अधिक की शेष पट्टे की अवधि (बेल्लारी जिले में छह और चित्रदुर्ग जिले में एक पट्टे की पहचान की गई);

(b) 0. 75 एम. एम. टी. और उससे अधिक के एम. पी. ए. पी. के साथ नीलाम किए गए श्रेणी-सी पट्टों और डालमिया पट्टों (एम. एल. संख्या 2010) में से प्रत्येक (दस पट्टों को अस्थायी रूप से पहचाना गया);

(c) नीलामी के लिए प्रस्तावित सभी नौ नए पट्टे, श्रेणी-ए/श्रेणी-बी पट्टे जो उनकी पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद नीलाम किए जा सकते हैं और पट्टे जो एमएमडीआर अधिनियम की धारा 10ए (2) (सी) और 10ए (2) (ए) के तहत दिए जा सकते हैं (वर्तमान में 10 पट्टों की पहचान की गई है); और

(d) जे. एस. डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड, लौह अयस्क का सबसे बड़ा खरीदार (इन जिलों में उत्पादित लौह अयस्क के लगभग 70 प्रतिशत का खरीदार) नंदलहल्ली से तुरानागल्लू में अपने संयंत्र और कम से कम 15 एम. एम. टी. या लौह अयस्क के वार्षिक परिवहन की क्षमता के साथ संबद्ध कन्वेयर प्रणाली के बीच है।

नीलाम लीज के संबंधित पट्टेदारों/सफल बोलीदाताओं को अधिकतम तीन महीने की अवधि के भीतर संरेखण को अंतिम रूप देना होगा।

मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) और/या वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत अनुमोदन के लिए क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा संबंधित पट्टेदारों/इस्पात संयंत्र की लागत पर अधिग्रहित/प्राप्त किया जाएगा। वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत आरओडब्ल्यू । अनुमोदनों के इस तरह के अधिग्रहण को खनन या संबंधित गतिविधियों के रूप में नहीं माना जाएगा, बल्कि सीईपीएमआईजेड के कार्यान्वयन के उद्देश्य से

माना जाएगा। राज्य सरकार और एम. ओ. ई. एफ. सी. सी. आवश्यक मंजूरी/अनुमोदन में तेजी लाएंगे।

पट्टेदार/इस्पात संयंत्र को आरओडब्ल्यू के तहत क्षेत्र उपलब्ध होने के बाद अधिकतम 18 महीने की अवधि के भीतर कन्वेयर प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता होगी, जिसमें विफल रहने पर संबंधित पट्टे में खनन कार्यों को निलंबित कर दिया जाएगा और कन्वेयर प्रणाली स्थापित होने के बाद ही फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।

(xi) उपरोक्त चिन्हित पट्टेदारों को व्यक्तिगत रूप से/सामूहिक रूप से रेलवे साइडिंग का निर्माण या उन्नयन करने की भी आवश्यकता होगी ताकि ऐसे खनन पट्टों में उत्पादित खनिज का बड़ा हिस्सा बंद पाइप कन्वेयर सिस्टम/रेलवे के माध्यम से ले जाया जा सके न कि सड़क के माध्यम से। जहां भी तकनीकी कारणों/व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण व्यक्तिगत पट्टेदार रेलवे साइडिंग का निर्माण/उन्नयन करने की स्थिति में नहीं हैं, वहां के. एम. ई. आर. सी. पूंजीगत लागत वसूली के आधार पर ऐसा निर्माण कर सकता है।

(xii) एम. एम. डी. आर. अधिनियम की धारा 10ए (2) (ए) और 10ए (2) (सी) के तहत स्वीकृत श्रेणी-ए/श्रेणी-बी पट्टों से 30 एम. एम. टी. का कुल उत्पादन अनुमत होगा अर्थात वर्तमान सीमा नीलाम किए गए पट्टों पर लागू नहीं होगी।

माननीय न्यायालय के निर्देशों के तहत एन. एम. डी. सी. लिमिटेड को अपने दो खनन पट्टों से सालाना 12 एम. एम. टी. उत्पादन करने

की अनुमति दी गई है। इसके एम. एल. संख्या 1111 के लिए अनुमोदित आर. एंड आर. योजनाओं के अनुसार एम. पी. ए. पी. 6.7 एम. एम. टी. है और एम. एल. संख्या 2396 के लिए 3.38 एम. एम. टी. है अर्थात इस माननीय न्यायालय के निर्देशों के तहत वर्तमान में अनुमत उत्पादन, अनुमोदित आर एंड आर योजनाओं में अनुमेय कुल एम. पी. ए. पी. से 2.55 एम. एम. टी. अधिक है। इसके अलावा, इस माननीय न्यायालय के निर्देशों के तहत एमएमएल को अपने दो खनन पट्टों की अनुमोदित आर एंड आर योजनाओं के अनुसार एमपीएपी से परे 3 एमएमटी या लौह अयस्क का उत्पादन करने की अनुमति दी गई है। जब भी संचालन श्रेणी-ए/श्रेणी-बी पट्टों और धारा 10ए (2) (ए) और 10ए (2) (सी) पट्टों से कुल उत्पादन 30 एम. एम. टी. से अधिक होने की संभावना है, तो एन. एम. डी. सी. लिमिटेड की दो खदानों से अतिरिक्त 2.5 एम. एम. टी. और एम. एम. एल. की दो खदानों से अतिरिक्त 3 एम. एम. टी. का उत्पादन आनुपातिक आधार पर कम करने की अनुमति होगी और इस हद तक कि सभी खनन पट्टों से कुल उत्पादन सीमा से अधिक न हो।

(xiii) नीलाम किए गए श्रेणी-सी और नीलाम किए गए डालमिया खनन पट्टों से 10 एम. एम. टी. के अतिरिक्त उत्पादन की अनुमति होगी और आर. एंड आर. योजनाओं के निर्देशों के अनुपालन, पट्टे के अनुसार अनुमेय एम. पी. ए. पी. और कन्वेयर बेल्ट सिस्टम और रेलवे साइडिंग की स्थापना के संबंध में शर्तों के अधीन होगी।

(xiv) यह माननीय न्यायालय डाउनहिल परिवहन के लिए कन्वेयर बेल्ट सिस्टम के प्रस्तावित निर्माण, जे. एस. डब्ल्यू. स्टील लिमिटेड

द्वारा कन्वेयर बेल्ट सिस्टम और रेलवे साइडिंग का निर्माण/उन्नयन पूरा होने के बाद ही उत्पादन में और वृद्धि पर विचार कर सकता है और रेलवे/कन्वेयर सिस्टम द्वारा अधिकांश खनिज का परिवहन सुनिश्चित करने का उद्देश्य हासिल किया जाता है, यानी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उत्पादन में और वृद्धि की अनुमति दी जाती है, सड़क द्वारा खनिज के परिवहन का वर्तमान स्तर इससे अधिक नहीं होगा।

19. सी. ई. सी. और विद्वान न्यायमित्र द्वारा दिए गए विभिन्न सुझावों और जिन शर्तों के अधीन योजना की मंजूरी मांगी गई है, उन्हें एफ. आई. एम. आई.-दक्षिणी क्षेत्र द्वारा सी. ई. पी. एम. आई. जेड. पर उठाई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए बेहतर ढंग से समझा जा सकता है।

20. संक्षेप में और मोटे तौर पर, एफ. आई. एम. आई.-दक्षिणी क्षेत्र की आपत्तियां तैयार की गई और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई योजना की बहुत व्यापक, अस्पष्ट और अस्पष्ट प्रकृति से संबंधित हैं, जो उक्त निकाय के अनुसार, लंबी अवधि की नींद के बाद तैयार की गई एक सतही कवायद है। एफ. आई. एम. आई. "दक्षिणी क्षेत्र" के अनुसार, योजना की तैयारी सही तरीके से शुरू की जानी चाहिए थीः बहुत पहले वर्ष 2012 में जब न्यायालय ने अपने 28 वें आदेश में कहा था कि, "विशेष उद्देश्य वाहन का गठन और योजना का प्रारूपण। खनन प्रभाव क्षेत्र के लिए व्यापक पर्यावरण योजना शायद अवैध खनन से तबाह हुए क्षेत्र के सुधार और पुनर्वास की प्रक्रिया का सबसे आवश्यक हिस्सा है। एफ. आई. एम. आई.-दक्षिणी क्षेत्र का यह भी तर्क है कि सी. ई. पी. एम. आई. जेड. में शामिल कुछ उपाय एस. पी. वी. का गठन करने वाले इस न्यायालय के आदेश और इसके पीछे के उद्देश्य की रूपरेखा से परे हैं। यह तर्क दिया जाता है कि निधियों का परिव्यय इस न्यायालय के पहले के आदेशों के

दायरे से परे है जो स्पष्ट रूप से विचार करता है कि विशेष निधि का कोई भी हिस्सा राज्य को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। भारत की समेकित निधि का उपयोग विशेष रूप से एस. पी. वी. से जुड़े उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। कई सामाजिक-आर्थिक परियोजनाएं जैसे पर्यटन और अवसंरचनात्मक उपाय; रेलवे लाइन बिछाना; औद्योगिक और चिकित्सा अवसंरचना की स्थापना में उन उद्देश्यों के लिए एस. पी. वाई. निधियों की तैनाती शामिल है जिन्हें सामान्य/सामान्य सरकारी कार्यों के दौरान निष्पादित किया जाना है। ऐसी गतिविधियों के संबंध में खर्चों को समेकित निधि से पूरा किया जाना आवश्यक है न कि विशेष निधि से। एफ. आई. एम. आई.-दक्षिणी क्षेत्र ने धन की उपलब्धता की सीमा पर भी विवाद किया है जो निगरानी समिति ने सी. ई. सी. के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए सी. ई. पी. एम. आई. जेड. में इंगित किया है। एफ. आई. एम. आई.-दक्षिणी क्षेत्र के अनुसार, निगरानी समिति के पास 31.03.2016 पर उपलब्ध कुल धनराशि रु. 8, एल 24 करोड़ और रु। 7, 000 करोड़, जैसा कि दावा किया गया है। चूंकि लगभग रु. का अधिशेष है। सी. ई. पी. एम. आई. जेड. में जो दिखाया गया है, उससे अधिक 1,800 करोड़ रुपये (आई. डी. 1) की लागत वाली इस योजना की मुख्य परियोजनाएं, अर्थात् कन्वेयर बेल्ट प्रणाली और रेलवे लाइनों और रेलवे साइडिंग का निर्माण, पट्टेदारों पर फिर से बोझ डालने के बजाय उपलब्ध निधियों से पूरा किया जा सकता है। 2, 900 करोड़। यह आगे तर्क देता है कि सीईसी की अंतिम रिपोर्ट दिनांक 3.02.2012 से, कन्वेयर बेल्ट, रेलवे साइडिंग जैसे लौह अयस्क के परिवहन की सुविधा में निवेश को एसपीवाई फंड से पूरा किया जाना था। अपनी आपत्तियों में, एफ. आई. एम. आई.-दक्षिणी क्षेत्र ने आगे तर्क दिया है कि तुमकुर, चित्रदुर्ग, देवनगेरे रेलवे लाइन भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया एक सामान्य उद्यम है और यह समझ में नहीं आता है कि बड़े पैमाने पर अवैध खनन से तबाह हुए तीन जिलों में पर्यावरण की बहाली के लिए यह कैसे फायदेमंद हो सकता है। हालांकि,

रु। रेलवे साइडिंग पर खर्च किए जाने वाले 500 करोड़ रुपये शुरू में एस. पी. वाई. द्वारा वहन किए जाने थे, सी. ई. सी. और विद्वान न्यायमित्र की संयुक्त रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए डी. पी. आर. पूंजीगत लागत वसूली के आधार पर होगी। इसी तरह, रुपये का निवेश। कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड और ऐसे अन्य निकायों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में औद्योगिक बुनियादी ढांचे में 750 करोड़ रुपये सुधारात्मक और शमनकारी उपायों के दायरे से बाहर हैं, जिसके लिए विशेष निधि से खर्च और निवेश की अनुमति अदालत ने दी थी। के. आई. ए. डी. बी. और ऐसे अन्य निकायों द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं ऐसे राज्य निकायों की सामान्य गतिविधियों से संबंधित हैं। जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना के बाद लौह अयस्क (या तो मौजूदा पट्टेदारों या भविष्य के पट्टेदारों द्वारा) की बिक्री आय पर किसी भी शुल्क को जारी रखने पर आपत्ति जताने के अलावा, एमआईएमआई-दक्षिणी क्षेत्र का यह भी तर्क है कि अगले 10 वर्षों के लिए जिला खनिज फाउंडेशन के पास जो धन उपलब्ध होगा, उसे सीईपीएमआईजेड में उल्लिखित वित्तीय अनुमान तैयार करने में ध्यान में नहीं रखा गया है।

21. कर्नाटक राज्य ने सी. ई. पी. एम. आई. जेड. का वस्तुतः लेखक होने के नाते न्यायालय को प्रस्तुत किया था कि कुछ शर्तों के अधीन सरकार की मंजूरी होनी चाहिए। कर्नाटक राज्य के सुझावों का विशेष महत्व है कि बी उत्पादन की सीमा को 30 एम. एम. टी. से बढ़ाकर 40 एम. एम. टी. और उसके बाद अतिरिक्त 20 प्रतिशत के मार्जिन के साथ 50 एम. एम. टी. तक बढ़ाया जाए और स्वयं पट्टेदारों द्वारा कन्वेयर बेल्ट प्रणाली और रेलवे साइडिंग के लिए भुगतान पर जोर दिया जाए। कर्नाटक राज्य के सुझावों द्वारा कुछ अन्य आनुषंगिक विशेषताओं/पहलुओं को शामिल किया गया है जो जहां तक एनएमडीसी खदानों का संबंध है, बिक्री आय में से योगदान की

दर के साथ-साथ उन खदानों से संबंधित हैं जिन्हें अंततः एमएमडीआरए की धारा 10ए (2) (बी) और (सी) के तहत पट्टे पर दिया जाएगा।

22. हमने इस मामले पर गहराई से विचार किया है। इस दृष्टिकोण को दर्ज करने के अलावा कि सीईपीएमआईजेड, इस स्तर पर, वास्तव में एक दृष्टि दस्तावेज की प्रकृति में है, जिसमें सभी ठोस उपायों, कदमों और प्रस्तावों पर बाद के चरण में काम किया जाना बाकी है, यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का चरण, हम योजना के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, सिवाय इसके कि यह कहने के कि जहां तक सामाजिक-आर्थिक उपायों का संबंध है, बहुत व्यापक और मोटे तौर पर, विभिन्न शीर्ष जिनके तहत बहाली और सुधार कार्य करने का प्रस्ताव है, जो बाद में अंतिम विवरण पर काम किए जाने के अधीन है, पर्याप्त रूप से व्यापक प्रतीत होता है। जहां तक एकीकृत खनन और रेलवे अवसंरचना, औद्योगिक और चिकित्सा अवसंरचना का संबंध है, हमारा विचार है कि एकीकृत खनन अवसंरचना और रेलवे अवसंरचना के हिस्से को छोड़कर, जहां तक ऊपर दिखाए गए चार्ट में उल्लिखित रेलवे साइडिंग और रेलवे उप लाइनों का उल्लेख है, बाकी अवसंरचनात्मक उपाय वर्तमान की प्रतीक्षा कर सकते हैं। इस मामले के विभिन्न आयामों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि इस स्तर पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर समग्र रूप से सी. ई. पी. एम. आई. जेड. को मंजूरी देने के बजाय, हमें इस मामले में अपने विचारों को तब तक रोकना चाहिए जब तक कि प्रत्येक व्यापक शीर्ष के संबंध में अधिक व्यापक विवरण उपलब्ध न हो जाए, जिसके तहत सुधारात्मक और शमनकारी उपाय किए जाने का प्रस्ताव है। हालाँकि, साथ ही, हमें एकीकृत खनन और प्रस्तावित रेलवे बुनियादी ढांचे के हिस्से, अर्थात् कन्वेयर बेल्ट प्रणाली के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी से अवगत कराना चाहिए। रेलवे साइडिंग और रेलवे उप-लाइनें। यह केवल एक बार है जब उपरोक्त बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर निर्णय लिया जाता है और उसके निष्पादन के मामले में

ध्यान देने योग्य प्रगति होती है, तो अन्य सुधारात्मक और शमनकारी सामाजिक-आर्थिक उपायों की कोई प्रासंगिकता हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह सीमित बुनियादी ढांचा है जो कन्वेयर बेल्ट, रेलवे साइडिंग और रेलवे उप-लाइनों के ऊपर इंगित किया गया है जो पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा जो सड़क द्वारा लौह अयस्क की खुली आवाजाही के कारण बना रहता है। लौह अयस्क की नियंत्रित और विनियमित आवाजाही के बाद ही अन्य सामाजिक-आर्थिक उपाय किए जाने चाहिए ताकि सार्थक परिणाम मिल सकें। जहां तक औद्योगिक बुनियादी ढांचे का संबंध है, बेल्लेरी, चित्रदुर्ग, तुमकुर क्षेत्रों में के. आई. ए. डी. बी. द्वारा पहले से किए जा रहे सभी उपाय जारी रह सकते हैं। इस स्तर पर ऐसी गतिविधियों में एस. पी. वी. को शामिल करना आवश्यक नहीं होगा। के. आई. ए. डी. बी. और अन्य निकायों द्वारा पहले से शुरू की गई ऐसी परियोजनाओं के लिए एस. पी. वी. से धन के हस्तांतरण पर हमेशा बाद के चरण में विचार किया जा सकता है। चिकित्सा अवसंरचना जिस पर रु। 950 करोड़ रुपये पर विचार किया गया है कि वर्तमान में इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे शब्दों में, पूरी सी. ई. पी. एम. आई. जेड. योजना को एक बार में अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है और इस तरह की मंजूरी पर विचार किया जा सकता है और चरणों में दी जा सकती है। प्रारंभिक गतिविधि की पहचान की गई, अर्थात्, कन्वेयर बेल्ट प्रणाली का निर्माण; रेलवे साइडिंग और रेलवे सब-लाइनों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

23. जहाँ तक निधियों के हस्तांतरण का संबंध है, एस. पी. वी. को हस्तांतरण के लिए निगरानी समिति के पास उपलब्ध निधियों की सटीक मात्रा के मुद्दे पर जाने के बिना भी, यह कहना पर्याप्त होगा कि निगरानी समिति के पास आज की तारीख तक उपलब्ध निधियाँ उन कार्यों के लिए अनुमानित लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक हैं जिन्हें न्यायालय द्वारा पर्यावरण की मरम्मत और बहाली के लिए प्राथमिकता

वाले कार्यों के रूप में पहचाना गया है। एक बार और विवरण. उपरोक्त कार्य के संबंध में तीन मद उपलब्ध हैं जो यह दर्शाते हैं कि वास्तव में क्या किया जाना प्रस्तावित है; यदि कार्य सी. ई. पी. एम. आई. जेड. में शामिल अन्य उपायों से स्वतंत्र रूप से किया जाना है, तो जो समय अवधि ली जाने की संभावना है. धन के स्रोत के संबंध में मुद्दा, अर्थात्, क्या राशि विशेष रूप से एस. पी. वाई. को हस्तांतरित की जाने वाली निधियों से होनी चाहिए या ऐसी लागत पट्टेदारों द्वारा वहन की जानी चाहिए, अदालत द्वारा तय की जा सकती है।

24. तदनुसार, वर्तमान में, हम विभिन्न भागों में योजना को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के संबंध में अपने विचारों को सुरक्षित रखते हुए मामले को समाप्त करते हैं; सटीक समय जिस पर ऐसे प्रत्येक चरण में काम किया जा सकता है और किया जाना चाहिए; ऐसे प्रत्येक चरण के लिए धन के स्रोत और ऐसे अन्य संबंधित मुद्दे। हम वर्तमान में कर्नाटक राज्य और सी. ई. सी. से मौजूदा पट्टों के संबंध में कन्वेयर बेल्ट प्रणाली के निर्माण की योजना के कार्यान्वयन और रेलवे साइडिंग और रेलवे उप-लाइनों के निर्माण से संबंधित परियोजना के विवरण के संबंध में एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का आह्वान करते हैं। जैसे ही उक्त प्रस्ताव/रिपोर्ट इस न्यायालय के समक्ष दायर की जाएगी, आगे के आदेशों का पालन किया जाएगा।

दिव्या पांडे आई. ए. को खारिज किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक **मनीष शर्मा** द्वारा किया गया है ।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है,एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।